2019 जनादेश के वैश्विक निहितार्थ

लेखक -शशि शेखर (सीईओ, प्रसार भारती)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

28 मई, 2019

"यह जनादेश भारत के लिए भू-राजनीतिक स्थान में आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए नए अवसर प्रदान करता है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्पष्ट और निर्णायक जनादेश भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक निर्णायक क्षण है। इसका प्रसार, जो एक आम चुनाव में सबसे अधिक मतदाताओं द्वारा किये गये मतदान और विजयी दल द्वारा जीते गए वोटों के हिस्से से प्रकट होता है, परिस्थितियों का अपना बहुत अनूठा सेट बनाता है।

इस परिप्रेक्ष्य में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत के पास 900 मिलियन से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 67% से अधिक ने मतदान किया अर्थात् 2019 के आम चुनाव में लगभग आधे अरब से अधिक लोगों ने भाग लिया था। जब हम इसकी तुलना दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र से करते हैं, अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी जनसंख्या 320 मिलियन से अधिक है, श्री मोदी द्वारा अर्जित जनादेश का परिमाण स्पष्ट हो जाता है।

यह भारत के लिए एक अनूठा क्षण है क्योंकि सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं के परिणामस्वरूप इस तरह का जनादेश आया है। ऐसे समय में जब दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां, अमेरिका और चीन, व्यापार युद्ध में व्यस्त हैं, यह जनादेश भारत के लिए भू-राजनीतिक स्थान में आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए नए अवसर प्रदान करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सही प्रक्षेपवक्र में लाने के लिए, हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए और रोजगार पैदा करने के लिए सरकार को इन अवसरों का लाभ उठाना होगा। इस तरह का जनादेश उम्मीदें पैदा करता है, साथ ही यह नेतृत्व को भी सही निर्णय लेने का अधि कार प्रदान करता है।

भू-राजनीति को बेहतर बनाना

मतदान का परिणाम भारत के लिए विश्व व्यवस्था में न सिर्फ अपना सही स्थान बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है, जहाँ भारत बहुपक्षीय प्लेटफार्मों पर होने वाले विचार-विमर्श में केवल भागीदार के रूप में रहता है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह का परिवर्तन हम देश में देखना चाहते हैं, यह उसे भी सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करेगा। भारत ने पिछले पाँच वर्षों में पेरिस समझौते के माध्यम से जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी कुछ पहलों में नेतृत्व का स्थान हासिल किया है।

भारत ने योग के वैश्विक प्रक्षेपण के माध्यम से अपनी सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ाया है, ताकि वह दुनिया को बता सके कि कैसे भारतीय आध्यात्मिकता एक बड़े बल का निर्माण कर सकती है। इसलिए, इस तरह के राजनीतिक जनादेश और वैश्विक परिस्थितियों के अनूठे सेट के साथ, यह उम्मीद और भी अधिक बढ़ गयी है कि भारत कई क्षेत्रों में भू-राजनीति को आगे बढ़ाने में सही नीति के साथ कार्य करेगा अर्थात् वैश्विक व्यापार से लेकर क्षेत्रीय संघर्ष तक उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों: जैसे-कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक दिशा तय करना, आदि।

आजादी के बाद भारत का लोकतंत्र एक बहुत ही अनूठा प्रयोग है, जो 75 साल के होने से कुछ ही साल दूर है। दुनिया में भारतीय संदर्भ और भारतीय प्रयोग के समानांतर कोई और लोकतांत्रिक देश नहीं है। हालांकि, वैश्विक मीडिया, विशेष रूप से प्रभावशाली पश्चिमी मीडिया आउटलेट, ने भारत को हमेशा कम कर के आंका है। लेकिन यह जनादेश वैश्विक मीडिया आउटलेट्स के दृष्टिकोण को बदलने में सहायक साबित होगा।

यह जनादेश श्री मोदी को आज विश्व के नेताओं के समूह के बीच पहले स्थान पर रखता है। जी20 राष्ट्रों के बीच मजबूत नेताओं की एक पूरी पीढ़ी उभरकर सामने आती रही है, जिसमें अमेरिका, जापान, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या दक्षिण अफ्रीका जैसे देश के नेता शामिल हैं, लेकिन केवल श्री मोदी ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में मतदाताओं की सबसे बड़ी संख्या द्वारा परीक्षण किए जाने का दावा कर सकते हैं।

यह जनादेश भारत को प्रमुख बहुपक्षीय प्लेटफार्मों पर एक बुलंद आवाज प्रदान करता है। यह भारत के लिए भारतीय मूल्यों को

आगे बढ़ाने और वैश्विक समस्याओं को हल करने के विशिष्ट भारतीय तरीकों की वकालत करने का अवसर पैदा करता है।

हितों की रक्षा करना

यह जनादेश तकनीकी-राष्ट्रवाद के एक नए पंथ के लिए भी कहता है। राजनीतिक जनादेश मांग करता है कि भारत उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों, जैसे-5 जी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, में आगे रहने के तरीकों और साधनों का विकास करे।

यह आह्वान करता है कि भारत एकल बेहतर और सुदृढ़ नीति के साथ सामने आये क्योंकि भारत अब प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के पाठ्यक्रम को स्थापित करने से भाग नहीं सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि भू-राजनीतिक गतिशीलता को भी आकार देगा।

भारत वैश्विक प्रौद्योगिकी की बड़ी कंपनियों के लिए सबसे बड़ा खुला बाजार है। जनादेश मांग करता है कि भारत अपने लोकतंत्र की ताकत और अपने बाजारों की शक्ति का लाभ उठाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वैश्विक मंच भारतीय राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचाने वाले नियमों का उपयोग न करे।

GS World टीम...

जी-20

क्या है और इसके कार्य क्या हैं?

- सितंबर, 1999 में जी-7 देशों के वित्त मंत्रियों ने जी-20 का गठन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के तौर पर किया था। यह मंच अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के साथ ब्रेटन वुड्स संस्थागत प्रणाली की रूपरेखा के भीतर आने वाले व्यवस्थित महत्वपूर्ण देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत एवं सहयोग को बढ़ावा देता है।
- यह समूह (जी-20) अपने सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और कुछ मुद्दों पर निर्णय करने के लिए प्रमुख मंच है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। जी-20 के नेता वर्ष में एक बार साथ मिलते हैं और बैठक करते हैं।
- इसके अलावा, वर्ष के दौरान, देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार लाने, वित्तीय नियमन में सुधार लाने और प्रत्येक सदस्य देश में जरूरी प्रमुख आर्थिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करते रहते हैं।
- इन बैठकों के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और विशेष मुद्दों पर नीतिगत समन्वय पर काम करने वाले कार्य समूहों के बीच वर्ष भर चलने वाली बैठकें भी होती हैं।
- ये देश विश्व के आर्थिक उत्पादन के 85 फीसदी का और जनसंख्या के 60 फीसदी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व बैंक और आईएमएफ के प्रमुख भी इस संगठन के सदस्य हैं। जी-20 की पहली बैठक दिसंबर, 1999 में बर्लिन में हुई थी।

स्थापना और शुरुआत

- जी-20 की शुरुआत, 1999 में एशिया में आए वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक के तौर पर हुई थी। वर्ष 2008 में जी-20 के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस समूह ने वैश्विक वित्तीय संकट का जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- इसकी निर्णायक और समन्वित कार्रवाई ने उपभोक्ता और व्यापार में भरोसा रखने वालों को शक्ति दी और आर्थिक सुधार के पहले चरण का समर्थन किया। वर्ष 2008 के बाद से जी-20 के नेता आठ बार बैठक कर चुके हैं।
- जी-20 समूह वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के साथ मिलकर काम करता है। कई अन्य संगठनों को भी जी-20 की प्रमुख बैठकों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

जी-20 के सदस्य देश

- जी-20 के सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का करीब 85 फीसदी, वैश्विक व्यापार के 75 फीसदी और विश्व की आबादी के दो-तिहाई से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सदस्य देशों के नाम

- अर्जेंटीना,ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ।

आवश्यकता क्यों?

- जी-20 का गठन उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ विचार-विमर्श और समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था।
- विश्व के सात प्रमुख औद्योगिक देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे पहले जी-20 में शामिल हुए।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. जी-20 की शुरूआत 1999 में यूरोप में आए वित्तीय संकट के पश्चात् वित्तमंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक के तौर पर हुई थी।
2. जी-20 की पहली बैठक बर्लिन में हुई थी।
3. 2020 में जी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 2 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

Q. Consider the following statements:

1. G-20 was launched as a meeting of the finance ministers and central bank governors after the financial crisis in Europe in 1999.
2. The first meeting of the G20 was held in Berlin.
3. G-20 summit, 2020 will be organized in Saudi Arabia.

Which of the above is / is the statement true?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) 2 and 3
(d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः- हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के जनादेश के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले वैश्विक प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)

Q. Evaluate the global impact on the Indian economy based on the mandate of the recently held Lok Sabha elections. (250 Words)

नोट : 27 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

Committed To Excellence